

शहीद भगत सिंह टाइम्स

वर्ष : 21 अंक : 31 सोमवार, 28 अप्रैल-4 मई, 2025, दिल्ली पृष्ठ: 4 मूल्य: 1 रुपया

सार संक्षेप

गाजियाबाद में वक्फ की जमीन हुई कब्जा मुक्त

कब्रिस्तान पर कई साल से था अवैध कब्जा, बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन नई दिल्ली/गाजियाबाद- गाजियाबाद में वक्फ की जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा था. शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक कई सालों से कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था और वहीं पर झुगियां बनाकर रह रहे थे. आरोप है कि स्थानीय दबंग और भूमिफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करवाया गया था.

भूमि को पहले कब्जा मुक्त कराया गया था. कुछ लोगों द्वारा भूमि पर फिर कब्जा कर लिया गया. भूमि को फिर कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है. उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है.

- प्रवीण गुप्ता, नाथब तहसीलदार

स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहां दबंगों की मदद से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया था. -खसरा नंबर 2211 कब्रिस्तान की भूमि है. कुछ लोगों ने दबंगों के सहयोग से कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर रखा था. कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया था. कब्जा करने के पश्चात यहां रह रहे लोग अवैध कार्य में लिप्त थे. प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है. पहले भी कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा हुआ था जिसको प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया था लेकिन कुछ वक्त बाद फिर कब्जा हो गया.

- अब्दुल वहीद, स्थानीय निवासी
कब्रिस्तान कमिटी के सचिव शहजाद ने बताया पहले भी कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है. 2021 में जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई थी. जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल के साथ कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है. जेसीबी आदि के माध्यम से कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है. कब्रिस्तान की जमीन पर अब बाउंड्री करने का काम किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान की भूमि में दाखिल ना हो सके और कब्रिस्तान की भूमि को अवैध कब्जे से बचाया जा सके.

पुराना सीलमपुर गांव रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी दर्जनों झुगियां पर चला बुलडोजर

दिल्ली- दिल्ली के पुराना सीलमपुर गांव रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी दर्जनों झुगियां पर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया. रेलवे की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने खुशी जतायी है. वहीं झुगी में रहने वालों में रोष है. भाजपा नेता व पूर्व निगम पार्षद ने बताया कि पुराना सीलमपुर गांव के रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से दर्जनों झुगियां बनायी गई थी, जिसमें अवैध गतिविधियां चलती थीं. काफी तादाद में अपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस झुगी बस्ती में रहते थे, जिसकी वजह से क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं होती थीं. लुटपाट स्मैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ गई थीं. इन घटनाओं में झुगी में रहने वाले लोग शामिल थे.

इन घटनाओं को लेकर स्थानीय आर डब्ल्यूए पदाधिकारी, मार्केट एसोसिएशन ने रेलवे को पत्र लिखकर अवैध झुगी पर कार्रवाई की मांग की थी. इसी मांग पर रेलवे ने शनिवार को रेलवे ने कार्रवाई की और अवैध रूप से बनाई गई झुगियों पर बुलडोजर चला दिया. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली रेलवे प्रशासन का इसके धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को सुना और उसे पर कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक की दूरी तक अवैध रूप से झुगियां बनाई गई थीं. वहीं इस कार्रवाई से झुगी बस्ती में रहने वाले लोगों में रोष है. उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के झुगी को गिरा दिया गया. उनकी छतों को छीन लिया गया. उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई. अब वह लोग अपने परिवार के साथ कहां रहेंगे, कहां जाएंगे. लोगों ने बताया कि वह लोग सालों से झुगी में रह रहे थे और छोटा-मोटा काम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे लेकिन अब सरकार ने उन्हें उजाड़ दिया है दर-दर भटकने को मजबूर कर दिया है.

सरकार ने माना सुरक्षा में हुई चूक

पहलगाम हमले पर संसद मर्माहत, सर्वदलीय बैठक दो घंटे चली राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, विपक्ष ने एक स्वर में कहा-सरकार आंतकियों के खिलाफ जो भी एक्शन ले, सब साथ

● नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैप्चर को नष्ट करने की मांग की। कहा की सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक दो घंटे चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इस बीच



खबर सामने आई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर का दौरा करेंगे। इसके साथ वह आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब राहुल गांधी अमेरिका गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें आतंकी हमले की खबर मिली तो

उन्होंने अपने अमेरिकी दूर को समाप्त कर फौरन वापस भारत लौटे। वहीं अमेरिका से लौटने के बाद राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक पर्यटकों से भी मुलाकात करेंगे। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब राहुल गांधी अमेरिका गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें आतंकी हमले की खबर मिली तो

कल्पना से बड़ी सजा देंगे आंतकियों को

बिहार में बोले पीएम मोदी- देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का किया है दुस्साहस

मधुबनी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही खुले मंच से आतंकियों और उनके आकाओं को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस हमले के पीड़ितों के साथ है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।

पहलगाम में आतंकी हमले की घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में इस हमले की साजिश रचने वालों और इसे अंजाम देने वालों को चेतावनी दी है कि उन्हें सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का



समय आ गया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि-कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है। वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना

जीवनसाथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुःख और आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निरथे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की सरजमीं से मैं पूरी दुनिया से यह कहना चाहता हूँ कि भारत इन लोगों की पहचान करेगा, उन्हें ढूँढेगा और हर आतंकी तथा उनकी मदद करने वालों को सजा देगा। हम उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक खदेड़ देंगे।

शांति यज्ञ का आयोजन

पूर्वी दिल्ली जी टीवी एंक्लेव में पहलगाम में हुए नृशंस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश द्वारा शांति यज्ञ का आयोजन रविवार को किया गया। जिसका मकसद मौत के गाल में समा गए लोगों की आत्मा को शांति देना है। शांति यज्ञ में विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह गौखक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संत राम प्रधान जी एवं अन्य लोगों ने यज्ञ में शामिल होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना में शामिल हुए।



न्याय केंद्र का शुभारंभ -सुंदर नगरी के राधा-कृष्ण मंदिर में कड़कड़डूमा अधिवक्ता परिषद की पहल

पूर्वी दिल्ली, (शिवकुमार अग्रवाल) कड़कड़डूमा इकाई के अधिवक्ता परिषद ने दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित प्राचीन श्री राधा-कृष्ण मंदिर (एफ-1, एफ-2 बंसीवाला) में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक न्याय केंद्र की स्थापना की। इस अवसर पर सेवा भारती से श्री रामभरोसे जी, अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री ललित नारायण सिंह, सचिव श्री अननीश शर्मा तथा प्रदेश से विशेष अतिथि श्री रणवीर सिंह उपस्थित रहे।

यह न्याय केंद्र आगामी प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित रहेगा। कार्यक्रम में स्थानीय



नागरिकों और समाजसेवियों की सक्रिय भागीदारी रही। अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को न्याय केंद्र की सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम के संचालन एवं व्यवस्था में कनिष्क जी, नेहा मिश्रा जी, प्रभाष गिरी जी, महिमा जी, चंदन तिलक, अमन माथुर जी, अजय शर्मा जी आदि का योगदान रहा। सामग्री

व्यवस्था की जिम्मेदारी योगेंद्र शर्मा जी ने संभाली, जल-पान की व्यवस्था अरुण जी ने की। फोटोग्राफी का कार्य शिव चरण जी ने किया, तथा बैटुक व्यवस्था कृष्ण गोपाल जी, तरुण गुप्ता जी और अननीश जी ने संभाली।

अन्य अधिवक्तागण जैसे रजनीश कपूर जी, प्रवीण जी, आरती रैना जी महिमा रस्तोगी जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने सभी कार्यकर्ताओं एवं बहनों की सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री ललित नारायण सिंह ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है।

अधिवक्ता परिषद कड़कड़डूमा इकाई द्वारा जिलाधीश महोदय को कार्यकारिणी पारित प्रस्ताव की प्रति सौंपी

पूर्वी दिल्ली (शिवकुमार अग्रवाल) अधिवक्ता परिषद, कड़कड़डूमा कोर्ट यूनिट ने दिल्ली के जिला उ. पूर्व जिला शहदरा तथा जिला पूर्व के माननीय जिला अधिकारी को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति सौंपी, जिसका शीर्षक था "Accountability of Independent Judiciary"

न्यायपालिका की भी कई विषय पर जवाबदेही तय हो और उनसे अनुरोध किया कि इस ज्ञापन को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत तक पहुंचाने की कृपा करें।

इस महत्वपूर्ण कार्य में दिवंगत प्रति के उपाध्यक्ष श्री रनबीर सिंह जी, महिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती



सरस्वती भरद्वाज जी कड़कड़डूमा कोर्ट इकाई अध्यक्ष श्री ललित नारायण सिंह जी, सचिव श्री अननीश शर्मा जी, श्री योगेंद्र शर्मा जी, श्री अरुण

कुमार जी श्री अमित गर्ग जी, डॉ. आकाश कौशिक जी, श्री अनिरुध चौहान जी, श्री अक्षय त्यागी जी श्री रिशभ त्यागी जी उपस्थित रहे।

जिसे 10 प्रतिशत भी समर्थन नहीं, वो निर्वाचित क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रावधान पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

● नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था करने वाली धारा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में कहा गया है कि इकलौते प्रत्याशी को विजेटा घोषित करना सही नहीं है। मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि लोग चाहें तो नोटा को भी वोट दे सकते हैं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एक ही प्रत्याशी हो तो मतदान करवाने की कोई जरूरत नहीं।

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी नाम की संस्था की तरफ से 2024 में दायित्व याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है। यह धारा कहती है कि जब कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में न हो, तो इकलौते प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित माना जाएगा। याचिका में कहा गया है कि अब



लोगों के पास नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है। भले ही नोटा को अधिक वोट पड़ने पर दोबारा चुनाव का प्रावधान नहीं है, फिर भी लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव

इकलौते प्रत्याशी को विजेटा घोषित करना सही नहीं

आयोग ने याचिका में रखी गई मांग को अनावश्यक और अव्यवहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है। आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने नोटा को एक विफल विचार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक के इतिहास में सिर्फ 9 लोग लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि लोग विधानसभाओं के लिए भी इस तरह निर्वाचित होते हैं। जस्टिस सूर्य कान्त और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता की तरफ से जताई गई एक आशंका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी के दबाव के चलते

कोई और नामांकन न करे, तो लोगों को बिना मतदान का अवसर दिए इकलौते प्रत्याशी को चुना हुआ मान लिया जाएगा। जस्टिस सूर्य कान्त ने कहा कि भारत में मजबूत और उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में कम से कम यह देखा जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार को कितने लोग समर्थन देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को 10 प्रतिशत लोग भी वोट नहीं देते, तो उसे संसद में भेजना क्या सही होगा? इस पर केंद्र सरकार के लिए पेश अर्दोनी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नया कानून नहीं बना सकता। इस तरह की व्यवस्था अगर लानी भी है, तो उसके लिए संसद को बहुत सारे लोगों की राय लेने के बाद कानून में बदलाव करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह कोई अनिवार्य आदेश नहीं दे रहा है। सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार की राय पूछ रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर ने 115 लोगों को किया गिरफ्तार

शिलांग : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मेघालय फ्रंटियर ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत- बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा और सीमा पार अपराधों के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल गई हैं। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि उनके जवानों ने कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया और 115 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 78 बांग्लादेशी और 37 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा, अवैध गतिविधियों में मदद करने वाले छह दलाल भी पकड़े गए, जिनसे आगे की कार्रवाई में मदद मिली। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारियां तस्करी और अवैध सीमा पार गतिविधियों से जुड़ी थीं। पृष्ठछाह में अहम सुराग मिले हैं।

